



04 - देश की रीढ़
अरावली का दर्द और
हम



05 - भाषा जोड़ती है, तोड़ती
नहीं

A Daily News Magazine

मोपाल
गुरुवार, 11 दिसंबर, 2025



मोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 101, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रु. 2



06 - एनएचआई ने 500
करोड़ रुपए का एस्टीमेट
बनाकर मेजा स्टेट...



07 - स्वास्थ्य सेवाओं के
व्यावसायिकरण के खिलाफ
चल रहा राष्ट्रीय अभियान

कहलुआ



subahsaverenews@gmail.com



facebook.com/subahsaverenews



www.subahsavere.news



twitter.com/subahsaverenews

शरद की सुबह

ये सर्दियाँ क्या हैं
मौत का
फ़हर हैं

गरीब की हड्डी-हड्डी
तड़प रही है
तन ढकने को
कपड़े भी नहीं है

पेड़ भी ठिठुर रहे हैं
पत्ते-पत्ते भी
मौत के ग्रास बन रहे हैं

साँस-साँस को
हवा बेचैन बना रही है
श्मशान की ओर
ले जा रही है

लेकिन बच्चे
फिर भी
नाच-कूद रहे हैं
अपनी मस्ती में डूबे
सर्दी को चुनौती
दे रहे हैं।

-दुर्गाप्रसाद झाला

पंजाब कांग्रेस में घमासान, सिद्धू अमृतसर पहुंचे

पत्नी बोलीं- राजा वडिंघ ने गुजरात में टिकट बेच महंगी गाड़ियां-जमीनें खरीदीं



अमृतसर (एजेंसी)। पंजाब कांग्रेस में मंचे घमासान के बीच पूर्व क्रिकेटर व कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू मुंबई से अमृतसर लौट आए हैं। सिद्धू के लौटते ही उनके अमृतसर स्थित घर में समर्थक भी जुटने लगे हैं। उनकी टीम मेंबर के तौर पर साथ रहने

वाले उनके घर के बाहर मौजूद हैं। उनकी पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू को लेकर पंजाब कांग्रेस नेताओं में हड़कप मचा हुआ है। नवजोत कौर ने कहा था कि सीएम बनने के लिए 500 करोड़ रुपए की अटेची चाहिए। कौर ने कांग्रेस प्रधान राजा वडिंघ, सांसद सुखजिंदर रंधावा, नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के अलावा कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। कौर ने ये भी कहा था कि अगर सिद्धू को सीएम चेहरा बनाएंगे तो ही वह एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे। कौर की बयानबाजी के बाद कांग्रेस उन्हें सस्पेंड कर चुकी है। हालांकि कौर ने कहा कि वह राजा वडिंघ को प्रधान ही नहीं मानती। हालांकि सिद्धू ने अभी तक इस पूरे मामले पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है।

महाविराट ओजोन छिद्र जल्द बंद होने से बढ़ी वैज्ञानिकों की उम्मीदें

ललित मोर्य

2020 से 2023 तक बने विशाल और लंबे छिद्रों की तुलना में 2025 का ओजोन छिद्र कम गहरा रहा और जल्द बंद हुआ, जिससे वैज्ञानिकों की उम्मीदें मजबूत हुई हैं।

2025 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र एक दिसंबर को बंद हो गया, जो 2019 के बाद सबसे जल्द बंद होने का रिकॉर्ड है।

इस साल ओजोन छिद्र आकार में छोटा और गहराई में कम रहा, जो ओजोन परत के सुधार की दिशा में सकारात्मक संकेत है।

यह घटना धरती और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक आशा की किरण है।

2025 में अंटार्कटिका के ऊपर बना ओजोन छिद्र एक दिसंबर को बंद हो गया, जो 2019 के बाद सबसे जल्द बंद होने का रिकॉर्ड है।

यह लगातार दूसरा साल है जब ओजोन छिद्र आकार में छोटा रहा और इसकी गहराई भी पहले की तुलना में कम रही। अच्छी खबर यह है कि 2020 से 2023 तक जो बड़े और लंबे समय तक बने रहने वाले ओजोन छिद्र देखे गए थे, उनकी तुलना में इस बार ओजोन परत में ज्यादा ओजोन मौजूद थी। यह संकेत देता है कि ओजोन परत धीरे-धीरे सुधार की राह में आगे बढ़ रही है।

कैसा रहा 2025 का ओजोन छिद्र?: अंटार्कटिका के ऊपर साल दर साल ओजोन छिद्र अगस्त से दिसंबर के बीच बनता है। इस साल इसने अगस्त के मध्य से बनना शुरू किया, जो सामान्य है। सितंबर की शुरुआत तक इसका आकार बढ़कर 2.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया।

देखा जाए तो यह आकार में विशाल जरूर है,

लेकिन 2023 में बने 2.61 करोड़ वर्ग किलोमीटर के विशाल छिद्र की तुलना में बेहद छोटा है।

इसके साथ ही सितंबर में ओजोन छिद्र का आकार सिमटना शुरू हो गया, लेकिन पूरा महीना यह डेढ़ से दो करोड़ वर्ग किलोमीटर के बड़े दायरे में बना रहा, जो करीब-करीब अंटार्कटिका के क्षेत्रफल जितना है। अक्टूबर के अंत तक भी यह इसी आकार में बना रहा। लेकिन नवंबर में यह अचानक तेजी से सिमटना शुरू हुआ, जिससे उम्मीद बनी कि यह बहुत जल्द बंद हो सकता है। आखिरकार एक दिसंबर को यह बंद हो गया, जो चार दशकों में सबसे जल्द बंद होने की घटनाओं में से एक है।

इस साल क्या था खास?: कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस द्वारा इस बारे में साझा जानकारी के मुताबिक हाल के वर्षों की तुलना 2025 के ओजोन छिद्र में कुछ असमान्य बातें सामने आईं। उदाहरण के लिए इस ओजोन परत का न्यूनतम स्तर पिछले वर्षों से बेहतर था। इसी तरह ओजोन की कमी (ओजोन मास डेफिसिट) भी सामान्य से कम रही। इन दोनों वजहों से इस साल ओजोन छिद्र कम गहरा और कम नुकसानदेह था।

इस दौरान वायुमंडल की ऊपरी परत यानी स्ट्रेटोस्फियर में हवाएं कमजोर रहीं, जिससे बाहरी इलाकों से ओजोन से भरपूर हवा अंदर आने लगी। इन सभी कारणों ने ओजोन परत को नुकसान कम पहुंचने दिया और गिरावट धीमी हुई।

2020 से 2023: लगातार बड़े और लंबे छिद्र: कॉपरनिकस द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भी ओजोन छिद्र अपेक्षाकृत छोटा रहा। यह सामान्य से देर से विकसित हुआ और औसत समय के भीतर बंद भी हो गया। लगातार चार वर्षों तक 2020 से

2023 के बीच बेहद बड़े और लंबे समय तक टिकने वाले ओजोन छिद्र देखने के बाद 2024 का यह छोटा और कम अवधि वाला छिद्र वैज्ञानिकों के लिए उम्मीद की किरण बना, मानो ओजोन परत धीरे-धीरे सुधार की ओर बढ़ रही हो।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने भी सितम्बर 2025 में जारी ओजोन बुलेटिन 2024 में कहा था कि पिछले साल ओजोन परत को होने वाला नुकसान कम रहा। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में अंटार्कटिका के ऊपर बनने वाला ओजोन छिद्र हाल के वर्षों की तुलना में छोटा रहा।

क्यों बने इतने बड़े ओजोन छिद्र?: इसके उलट, 2020, 2021, 2022 और 2023 के ओजोन छिद्र असाधारण रूप से बड़े और लंबे समय तक बने रहे। इनमें से 2020 का ओजोन छिद्र सबसे देर से 28 दिसंबर 2020 को बंद हुआ, जो अब तक के सबसे देर से बंद होने वाले मामलों में से एक था। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में ओजोन छिद्र के बड़े होने की कई वजहें रही। इनमें से एक हुंगा टोंग-हुंगा ज्वालामुखी में 2022 में हुआ विशाल विस्फोट था, जिसने स्ट्रेटोस्फियर में पानी और राख की भारी मात्रा पहुंचाई। इसी तरह जलवायु परिवर्तन भी इसकी वजह बन रहा है। जलवायु में आता बदलाव ऊपरी वायुमंडल को ठंडा कर देता है, और ठंड जितनी ज्यादा होती है, ओजोन छिद्र बनने की आशंका भी उतनी अधिक होती है।

आमतौर पर सर्दियों में अंटार्कटिका के ऊपर बहुत ठंड होती है। इस दौरान बादल जम जाते हैं और तेज हवाएं एक ठंडा 'पोलर वॉर्टेक्स' बना देती हैं। वसंत में जब सूरज उगता है तो ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन (जैसे सीएफसीएस आदि)

बादलों की सतह पर सूरज की रोशनी के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं और ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं।

गौरतलब है कि 1980 के दशक में जब वैज्ञानिकों ने पहली बार चेतावनी दी कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन तेजी से खत्म हो रही है, तो दुनिया हरकत में आई।

उम्मीद की किरण: इसके बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर दुनिया के करीब सभी देशों ने हस्ताक्षर किए और ओजोन-नाशक रसायनों पर रोक लगाई गई। इन्हीं का नतीजा था कि धीरे-धीरे ओजोन परत में सुधार आने लगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक ओजोन-नाशक रसायनों (ओडीएस), जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध से ओजोन परत के धीरे-धीरे ठीक होने का रास्ता खुल गया। रिपोर्ट के मुताबिक, इन रसायनों पर रोक ने वैश्विक तापमान में लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस की अतिरिक्त बढ़ोतरी को भी रोकने में मदद की है।

वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि 2050 से 2066 के बीच यह परत पूरी तरह ठीक हो सकती है। 2025 का छोटा और जल्द खत्म हुआ ओजोन छिद्र यह दर्शाता है कि हम सही दिशा में हैं, लेकिन मौसम और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक घटनाएं अब भी ओजोन परत को प्रभावित कर रही हैं। यह खबर धरती और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सकारात्मक संदेश है कि अगर दुनिया मिलकर काम करे, तो बड़े से बड़े पर्यावरण से जुड़े संकट भी टाले जा सकते हैं।

(‘डाऊन टू अर्थ’ हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सीएम डॉ. यादव ने की लोक निर्माण विभाग की समीक्षा

हर सड़क, हर पुल, हर परियोजना-जनता के जीवन को सरल और सुरक्षित बनाने की हमारी संकल्पना : मुख्यमंत्री



भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ

मोहन यादव ने कहा है कि सड़कें केवल यातायात का माध्यम नहीं, बल्कि विकास, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और सामाजिक-सांस्कृतिक प्रगति का आधार हैं। विभाग का उद्देश्य प्रत्येक निर्माण कार्य को सिर्फ एक तकनीकी परियोजना के रूप में नहीं, बल्कि जनता के जीवन स्तर को सुधारने वाले साधन के रूप में देखना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गुणवत्ता, पारदर्शिता और नवाचार के साथ प्रत्येक परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, यही प्रयास 'लोक निर्माण से लोक कल्याण' की भावना को साकार करते हैं। यह निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिये।

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने विभाग द्वारा 'लोक निर्माण से लोक कल्याण' की भावना को धरातल पर उतारने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश की आधारभूत संरचना का विकास ही जनकल्याण का आधार है और विभाग ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर सड़क, हर पुल, हर परियोजना जनता के जीवन को सरल और सुरक्षित बनाने की हमारी

संकल्पना का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि मेट्रोपॉलिटन परिया और समीपवर्ती क्षेत्रों में राजमार्गों का घनत्व बढ़ायें। पूरे प्रदेश को समन्वित कर समग्र विकास पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही जबलपुर और ग्वालियर को भी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। शहरी, ग्रामीण एवं औद्योगिक क्षेत्रों सभी को अधोसंरचना विकास का लाभ प्राप्त हो इस आधार पर प्रस्ताव की परिकल्पना की जाये। उन्होंने कहा कि राजमार्गों का घनत्व राष्ट्रीय स्तर के समीप ले जाने के लिए विजुन डॉक्यूमेंट के आधार पर प्रस्ताव तैयार करें। प्रस्ताव में स्थानीय मांगों और सुझावों को यथोचित स्थान दिया जाये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अगर मुख्य सचिव क्षेत्रों के समग्र विकास अनुसार कार्ययोजना का निर्धारण करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि शहरी विकास की इंटीग्रेटेड पॉलिसी के निर्माण में लोक निर्माण विभाग को भी शामिल किया जाये। उन्होंने कहा कि अधोसंरचना विकास में पर्यावरण समन्वय का विशेष ध्यान रखा जाये। सतत संवहनीय विकास के लिए सूरत के डायमंड पार्क की तर्ज में भवनों का निर्माण ग्रीन बिल्डिंग संकल्पना पर किया जाये। बिजली और पानी की

बचत सुनिश्चित की जाये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भवन निर्माण में वास्तु-विज्ञान का ध्यान रखा जाये। ताकि सूर्य की रोशनी, हवा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित हो और ऊर्जा की बचत को जा संके।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एक्सप्रेस-वे आधुनिक समय की मांग है। इन अधोसंरचनाओं के विकास में ग्रामीण क्षेत्र की सुविधाओं का ध्यान रखा जाये। आवश्यकतानुसार फ्लाई-ओवर, अंडर-पास, सर्विस लेन को प्रस्ताव में शामिल करें। बैठक में बताया गया कि सितम्बर-2028 के कार्य प्राथमिकता से किए जा रहे हैं। प्रस्तावित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। दिसम्बर माह के अंत तक कार्य प्रारंभ हो जायेगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि कार्यों को जून-2027 तक पूर्ण किया जाये। बैठक में बताया गया कि लोकपथ ऐप में प्राप्त 12 हजार 212 शिकायतों में से 12 हजार 166 का निराकरण किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोकपथ ऐप के उत्कृष्ट उपयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोकपथ ऐप में रियल टाइम सड़क की स्थिति को भी अपडेट किया जाये।

दिवाली को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। यूनेस्को ने दिवाली को अमूर्त विश्व धरोहर घोषित किया। यूनेस्को ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन की ईटैनिजबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त विश्व धरोहर की सूची जारी की। इसमें घाना, जॉर्जिया, कांगो, इथियोपिया और मिस्र सहित कई देशों के सांस्कृतिक प्रतीक भी शामिल हैं। इस पर पीएम मोदी ने कहा, 'दिवाली हमारी सभ्यता की आत्मा है।' भारत की 15 अमूर्त विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। इसमें दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, वैदिक मंत्रोच्चार, रामलीला, छऊ नृत्य भी शामिल हैं। ये फैसला उस समय आया है, जब दिल्ली में यूनेस्को की इंटर-गवर्नमेंटल कमेटी फॉर ईटैनिजबल हेरिटेज की 20वाँ बैठक की मेजबानी कर रही है।

पीएम मोदी बोले- दिवाली हमारी सभ्यता की आत्मा



इस त्योहार की वैश्विक लोकप्रियता में और भी वृद्धि होगी

पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर बधाई देते हुए लिखा, भारत और दुनियाभर के लोग उत्साहित हैं। हमारे लिए दिवाली, संस्कृति और प्रकृति से जुड़ी है। यह हमारी सभ्यता की आत्मा है। यह ज्ञान और धर्म का प्रतीक है। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किए जाने से इस त्योहार की वैश्विक लोकप्रियता में और भी वृद्धि होगी। प्रभु श्री राम के आदर्श हमें शाश्वत रूप से मार्गदर्शन करते रहें।

सत्य नडेला बोले- भारत का एआई मॉडल कॉपी नहीं हो सकता

मुंबई। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला ने अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी से मुलाकात की। दोनों ने टेक्नोलॉजी के भविष्य, खासकर एआई पर चर्चा की। अडाणी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि नडेला से मिलना हमेशा सुखद होता है। उन्होंने आगे लिखा कि सत्य नडेला खुद जो एक्स एक्स बना रहे हैं, उसका डेमो भी दिखाया। यह देखकर लगा कि सचमुच के बड़े लीडर कितने हाथों-हाथ काम करते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी के भविष्य वाली बातें बहुत कीमती हैं। जैसे-जैसे एआई का जमाना आ रहा है और फिजिकल-डिजिटल दुनिया एक हो रही है, हम 360° पार्टनरशिप बनाने के लिए बहुत उत्साहित हैं।



जैसे-जैसे एआई का जमाना आ रहा है और फिजिकल-डिजिटल दुनिया एक हो रही है, हम 360° पार्टनरशिप बनाने के लिए बहुत उत्साहित हैं।

बिहार में ‘1 घर-1 मीटर’ का नियम लागू

फ्री बिजली के लिए नहीं चलेगी चालाकी, दिखावे होंगे जमीन बंटवारे के कागजात

पटना (एजेंसी)। बिहार सरकार द्वारा 125 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने की घोषणा के बाद बिजली कनेक्शन लेने वालों की होड़ सी लग गई है। बड़ी संख्या में उपभोक्ता यह सोचकर नया कनेक्शन लेने के लिए आवेदन करने लगे हैं कि अगर एक ही घर में दो-तीन या चार कनेक्शन हो जाएं, तो उन्हें 125 यूनिट के हिसाब से अधिक फ्री बिजली मिल



जाएगी। इसी सोच के तहत कई लोग अलग-अलग परिवार के सदस्यों के नाम से एक ही मकान के लिए नये कनेक्शन का आवेदन कर रहे हैं।

नया कनेक्शन लेने से बचते थे लोग- पहले स्थिति इसके उलट थी। लोग नया कनेक्शन लेने से बचते थे क्योंकि जितनी बिजली खपत होती थी, उतना बिल तो देना ही पड़ता था। साथ ही मीटर की संख्या बढ़ने पर फिक्स चार्ज भी बढ़ जाता था।



सागर में लैंडिंग के दौरान ट्रेनी विमान क्रैश,फिसलकर रफ एरिया में पहुंचा

सागर (नम्र)। मध्य प्रदेश के सागर जिले के ढाना स्थित एयर स्ट्रिप पर बुधवार दोपहर में लैंडिंग के दौरान एक ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। विमान के ब्रेक न लगने से वह रनवे से फिसलकर रफ एरिया में चला गया। विमान के रुकते ही वह डिसबैलेंस होकर एक तरफ झुक गया। हालांकि हादसे में पायलट पूरी तरह सुरक्षित हैं।

जानकारी अनुसार सागर के ढाना हवाई पट्टी पर बुधवार प्रशिक्षु विमान उतरते समय हादसे का शिकार हो गया। डबल सीटर सेसना विमान ने जैसे ही लैंडिंग के दौरान रनवे को छुआ तो उसके ब्रेक नहीं लगे। वह रनवे पर फिसलते हुए तय एरिया से आगे बढ़कर रफ एरिया में पहुंच गया। यहां विमान एक झटके से रुका और उसका संतुलन बिगड़ गया। वह एक तरफ झुका और उसकी नोज जमीन से टकरा गई। हादसे में विमान में हल्की टूट-फूट की जानकारी दी जा रही है।

विमान हादसे के दौरान रनवे पर एयर एंबुलेंस मौजूद थी- बता दें कि जब ट्रेनी विमान हादसे का शिकार हुआ उस समय रनवे पर एक एयर-एंबुलेंस भी मौजूद थी। एयर एंबुलेंस से बीडीएस के एक घायल जवान को एयर लिफ्ट कर मुंबई भेजा जाना था। इसी दौरान रनवे पर प्रशिक्षु विमान उतरते समय हादसे का शिकार हो गया

विमान को देख स्टाफ दौड़ पड़ा पायलट को निकाला

ढाना एयर स्ट्रिप पर जैसे ही विमान रफ एरिया में पहुंचकर डिसबैलेंस हुआ, उस समय रनवे पर काफी लोग मौजूद थे। स्टाफ में विमान को झुकते देख हड़कंप मच गया और पूरा स्टाफ विमान की तरफ दौड़ पड़ा। स्टाफ ने पायलट को विमान से सुरक्षित बाहर निकाला और तत्काल एंबुलेंस से अस्पताल भेजा। फायर लॉरी को भी तत्काल एक्टिव कर दिया गया था। हालांकि शुरु रहा कि कोई हादसा नहीं हुआ।

बच्ची से निर्भया जैसी दरिंदगी, प्राइवेट पार्ट में रॉड घोंपी आलीराजपुर के युवक ने गुजरात में की रेप की वारदात, खींचकर झाड़ियों में ले गया

आलीराजपुर (नम्र)। गुजरात के राजकोट जिले के आटकोट के पास कानपर गांव की सीमा में दिल्ली निर्भया कांड जैसी बेहद क्रूर और अमानवीय घटना सामने आई है। खेत में खेल रही 6 साल की मासूम बच्ची को एक खेत मजदूर झाड़ियों में खींच ले गया। दुष्कर्म के बाद उसके साथ की हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। आरोपी मध्यप्रदेश के आलीराजपुर का रहने वाला है। घटना के कुछ ही घंटों में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस 7 दिन की रिमांड के लिए कोर्ट में उसे पेश करेगी।

10 सदियों की लाइनअप, बच्ची ने आरोपी को पहचाना- राजकोट ग्रामीण एसपी विजय सिंह गुर्जर के मुताबिक पीड़िता मूल रूप से दाहोद जिले की रहने वाली है। परिवार खेतों में मजदूरी करता है। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद बच्ची के प्राइवेट पार्ट में रॉड घोंप दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची दर्द से कराहती रही, लेकिन आरोपी उसे वहीं लहलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया।

पुलिस ने 10 टीम बनाकर 10 किलोमीटर के दायरे में लगे सीसीटीवी खंगाले। 10 सदिय्थ सामने आए। चाइल्ड काउंसलर, महिला पुलिस और डॉक्टर की मौजूदगी में बच्ची ने आरोपी रामसिंह तेजसिंह की पहचान की।

4 दिसंबर को क्या हुआ था?– आरोपी पास के खेत



में मजदूरी करता था। उसी खेत में पीड़िता के मामा-मामी भी काम करते थे। दोपहर करीब 12 बजे बच्चे खेल रहे थे। आरोपी ने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर पानी की टंकी के पीछे ले गया। रेप की कोशिश असफल होने पर उसने प्राइवेट पार्ट में रॉड घोंप दी। बच्ची की हालत बिगड़ते ही वह भाग निकला। परिजनों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, तब पुलिस को सूचना दी गई।

आरोपी खुद 13 साल की बेटी का पिता- आरोपी रामसिंह (30) मध्यप्रदेश के अलीराजपुर का निवासी है। उसके दो बेटे और एक 13 साल की बेटी है। घटनास्थल

से एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। सरकार के निर्देश हैं कि जल्द चार्जशीट दाखिल कर सख्त सजा दिलाई जाए।

मन में अचानक आई विकृति, कोई पूर्व योजना नहीं- पुलिस के अनुसार आरोपी ने पहले से कोई योजना नहीं बनाई थी। बच्ची को देखकर उसमें अचानक विकृति उत्पन्न हुई। आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। फिलहाल पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर और धाराएं जुड़ सकती हैं।

घटना 4 दिसंबर की, मामला अब क्यों सामने आया?– शुरुआत में परिजनों को लगा कि बच्ची खेलते समय गिर गई है। अस्पताल में इलाज चलने के दौरान 24 घंटे महिला कॉन्स्टेबल तैनात रही। जब डॉक्टरों ने पुष्टि की कि बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, तब एफआईआर दर्ज की गई। घटना के बाद आटकोट और आसपास के इलाकों में आक्रोश फैल गया है। लोग दोषी को फांसी जैसी सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं।

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूला जुर्म- पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। जब बच्ची ने विरोध किया तो उसने रॉड घोंप दी। आरोपी ने बच्ची का मुंह दबाकर वारदात को अंजाम दिया।

शशि थरूर ने वीर सावरकर अवॉर्ड लेने से इनकार किया

- बोले-आयोजकों ने बिना पूछे नाम घोषित किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में वीर सावरकर अवॉर्ड को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने कहा- मैं ये अवॉर्ड लेने नहीं जा रहा हूं। मुझे इसके बारे में केरल में रहते हुए मीडिया रिपोर्ट्स से ही जानकारी मिली। कांग्रेस सांसद ने कहा कि आयोजकों ने बिना पूछे मेरा नाम घोषित किया है। ऐसे में दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। वहीं, अवॉर्ड देने वाले एनजीओ ने थरूर के दावे को गलत बताया। दि हिमारेज रुरल डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया के संस्थापक अजी कृष्णन ने दावा किया कि वे एक महीने पहले थरूर से उनके घर पर मिले थे।



दिल्ली हाईकोर्ट बोला- इंडिगो फेल हुई तो सरकार ने क्या किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने पूछा कि जब एयरलाइन फेल हो गई थी, तब सरकार ने क्या किया। कैसे फ्लाइट्स की टिकट की कीमतें 4-5 हजार रुपए से बढ कर 30,000 रुपए तक कैसे पहुंच गई। अन्य

एयरलाइंस ने इसका फायदा कैसे उठाया। आपने क्या कार्रवाई की? आपने ही स्थिति को इस हाल तक पहुंचने दिया।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदला की डिविजन बेंच जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई कर रही थी। इसमें मांग की गई थी कि इंडिगो संकट की स्वतंत्र न्यायिक जांच की जाए और जिन लोगों की फ्लाइट रद्द हुई या जो एयरपोर्ट पर फंसे उन्हें मुआवजा दिया जाए।

बैतूल के कारीगर बलदेव वाघमारे को मिला राष्ट्रपति से अवॉर्ड

भोपाल/बैतूल (नम्र)। जिले के शिल्पकार बलदेव वाघमारे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें आदिवासी भरेवा शिल्प के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार भरेवा शिल्प को राष्ट्रीय पहचान दिलाता है, जिसे हाल ही में जीआई टैग भी मिला है।

कौन हैं बलदेव वाघमारे- बलदेव वाघमारे, जो बैतूल जिले के हैं, पारंपरिक जनजातीय भरेवा शिल्प के जाने-माने कारीगर हैं। यह शिल्प गोंड समुदाय की एक उप-जनजाति से जुड़ा है। भरेवा कलाकार देवताओं के प्रतीकात्मक चित्र बनाते हैं। वे अंगुठियां और खंजर जैसे आभूषण भी बनाते हैं, जो गोंड परिवारों में शादी-ब्याह के रीति-रिवाजों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। कुछ खास आभूषण, जैसे कलाईबंद और बाजूबंद, आध्यात्मिक गुरुओं या पारंपरिक चिकित्सकों के लिए बनाए जाते हैं।



देश में चुनिंदा कारीगर- भरेवा शिल्प के कारीगरों की संख्या कम हो रही थी, लेकिन बलदेव वाघमारे ने इस गिरावट को रोकने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बैलगाड़ी, मोर के आकार के दीपक, घंटियां और पायल जैसी सजावटी चीजें बनाई हैं। इन कलाकृतियों ने भरेवा शिल्प को अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी पहचान दिलाई है।

क्या होता है भरेवा का अर्थ- स्थानीय भाषा में 'भरेवा' का मतलब

कंगना रनोट बोलीं- पीएम मोदी दिलों को हैक करते हैं ईवीएम को नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही जारी है। लोकसभा में चुनाव सुधार और एसआईआर पर चर्चा जारी है। भाजपा सांसद कंगना रनोट ने कहा विपक्ष ईवीएम हैक करने की बात करता है ये भूल गए हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी दिलों को हैक करते हैं। वहीं सपा की डिंपल यादव ने कहा कि सरकार एसआईआर के जरिए एनआरसी लागू कर रही है।

कंगना बोलीं- एक देश एक चुनाव लागू किया जाए- भाजपा सांसद कंगना रनोट ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि ये हर दिन एसआईआर, एसआईआर आकर हंगामा कर रहे थे। दिल दहल जाता था इनको देखकर। कल राहुल गांधी जी जब बोल रहे थे, बार-बार वही खादी में धागा है, धागे से कपड़ा है, करते रहे।



हनुमानगढ़ में बवाल, किसानों-पुलिस में झड़प

- गाड़ियों में आग लगाई, आंसू गैस के गोले दागे

हनुमानगढ़ (एजेंसी)। हनुमानगढ़ में पुलिस और किसानों में झड़प हो गई। किसानों ने ट्रैक्टरों से निर्माणधीन एथेनॉल फैक्ट्री की दीवार को तोड़ दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। किसानों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे।

मामला टिब्बी इलाके के राठी खेड़ा गांव का बुधवार का है। किसान के समर्थन में पहुंचे कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया लाठीचार्ज में घायल हो गए। उन्हें हनुमानगढ़ जिला अस्पताल ले जाया गया। प्रशासन ने टिब्बी करबे और आसपास के गांवों में इंटरनेट बंद कर दिया। स्कूल और दुकानें भी बंद है। इससे पहले फैक्ट्री के विरोध में बुधवार को किसानों ने एसडीएम कार्यालय के सामने सभा की।



एमपी-राजस्थान में शीत लहर 43 शहरों में पारा 10 डिग्री से कम

- हिमाचल के शिंकुला दर्रा में बर्फबारी, यूपी-बिहार के 30 जिलों में घना कोहरा

उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद बना 10 फीट ऊंचा शिवलिंग

नई दिल्ली/भोपाल/लखनऊ/देहरादून/जयपुर (एजेंसी)। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बीच मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन शीतलहर का अलर्ट है। बीती रात प्रदेश में सबसे कम तापमान शहडोल के कल्याणपुर में 4.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, इंदौर समेत 25 शहरों में पारा 10 डिग्री से कम रहा।

वहीं, राजस्थान में कड़के की सर्दी पड़ रही है। प्रदेश में 10 दिसंबर तक कोल्ड वेव का असर रहेगा। 18 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में रहा। सबसे कम तापमान फतेहपुर में 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इधर उत्तर प्रदेश में बाराबंकी, गोंडा समेत 20 जिलों में बुधवार सुबह भी घना कोहरा छाया रहा। कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य रही। वहीं, बिहार के 10 जिलों में भी कोहरे से विजिबिलिटी जीरो रही। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिला के शिंकुला दर्रा में बर्फबारी हुई। शिंकुला टॉप पर 6 इंच तक बर्फ पड़ी। तापमान में 3-4 डिग्री तक की गिरावट आई है।



चमोली में प्राकृतिक रूप से बर्फ से बने शिवलिंग के रूप में महादेव विराजमान हैं- उत्तराखंड के चमोली जिले में चीन सीमा से सटा टिम्परसेण महादेव एक रहस्यमय और अद्भुत स्थल है। यहां प्राकृतिक रूप से बर्फ से बने शिवलिंग के रूप में महादेव विराजमान हैं, जो अमरनाथ की गुफा में बर्फोंले बाबा के समान दिखाई देते हैं। दिसंबर से मार्च तक यहां बर्फ से शिवलिंग का निर्माण होता है, जिस पर पहाड़ से लगातार जलधारा गिरती रहती है। यह दृश्य श्रद्धालुओं को अमरनाथ की याद दिलाता है और एक अनूठा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है।

राहुल संसद सत्र के बीच जर्मनी जाएंगे

- भाजपा बोली- उनके लिए एलओपी मतलब लीडर ऑफ पर्यटन, प्रियंका का जवाब- पीएम भी आधे समय विदेश में रहते हैं

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आगामी जर्मनी यात्रा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा ने बुधवार को संसद के शीतकालीन सत्र के बीच राहुल की विदेश यात्रा को लेकर उनकी आलोचना की है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा- राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि 'एलओपी' का मतलब 'लीडर ऑफ पर्यटन' होता है। वे लीडर ऑफ पार्टीइंग (पार्टी करने वाले नेता हैं)। संसद सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा, फिर भी राहुल 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी में रहेंगे। वहीं, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम का आधा समय विदेश में बिताते हैं।



संपादकीय

ऋणम् कृत्वा, घृतम् पीवेत् !

गले-गले तक कर्ज में डूबी मध्यप्रदेश सरकार अब दूसरे राज्यों में अपनी सम्पत्तियां बेच कर इसकी भरपाई करने का प्रयत्न करेगी। यह स्थिति इसलिए बनी है कि मोहन यादव सरकार लगभग हर माह कर्ज उठा रही है और इस कर्ज की कितने चुकाने में भी सरकार का दम निकल रहा है। इसी संदर्भ में चिंताजनक खबर यह है कि विविध विभागों ने सभी विभागों को पर त्रिखरक जानकारी मांगी है, जिसमें पूछा है कि किस राज्य में कितनी संपत्ति किस रूप में है? उसका मूल्य क्या है? अगर किसी प्रॉपर्टी का कोर्ट में केस चल रहा है, किसी तरह का विवाद है तो इसकी भी जानकारी दी जाए। इन जानकारियों के आधार पर लोगों ने संपत्ति प्रबंधन विभाग पुरे देश में फैली इन संपत्तियों का व्यापक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस कयावद का मकसद प्रदेश के बाहर मौजूद संपत्तियों को बेचकर या किराये पर देकर राशि जुटाना है। विभाग इन संपत्तियों के मुदीकरण यानी मॉनेटाइजेशन की रणनीति बनाएगा। प्रदेश के वायनाड से लेकर मुंबई के पेशा इलाकों और उत्तर प्रदेश के झांसी तक, मध्य प्रदेश सरकार की करोड़ों-अरबों की संपत्तियां हैं, जो या तो विवादों में फंसी हैं या उनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। मौलतब है कि राज्य सरकार इस वक्त कुल 4 लाख 64 हजार करोड़ के कर्ज में डूबी है और चार्वाक निर्माण 'ऋणम कृपा घुमन पर्वत' की तर्ज पर हर माह नया कर्ज उठाना जा रहा है। इसी प्रकार लाड़ली बहना योजना सरकार के गले पड़ चुकी है। ऐसे में कुछ प्रॉपर्टी का सौदा भी लगभग हो चुका है। मप्र सरकार की ये प्रॉपर्टियां केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में फैली हैं। इनमें केरल की बीनाची इस्टेट का सौदा तो लगभग तय माना जा रहा है। इसी प्रकार मुंबई के गोरेगांव क्षेत्र में मप्र सरकार की लगभग 2.5 एकड़ (10,460 वर्गमीटर) जमीन है, जिस पर टेक वेंचर लिमिटेड नामक कंपनी का कब्जा है। इस जमीन का बाजार मूल्य 1.28 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर से भी अधिक है। सूचों के मुताबिक, इस कंपनी पर सरकार का 77.15 करोड़ रुपए का किराया बकाया है। उसे बेदखल किया जा रहा है। नागपुर में मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम ने 1956 में रक्षा विभाग से 37,107 वर्गफुट जमीन खरीदी थी, लेकिन 2018 में स्थानीय भूमि अभिलेख अधिकारी ने इसे महाराष्ट्र सरकार के नाम कर दिया। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इस जमीन पर मप्र का हक बहाल हुआ है। इस जमीन की कीमत 150 करोड़ रुपए लगाई गई है। उप के झांसी में झांसी में मध्य प्रदेश सरकार की करीब 19 एकड़ जमीन है, जिस पर वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार का कब्जा है। इसका स्वामित्व फिर से हासिल किया जा रहा है। झांसी में ही बस डिपो की 1373.80 वर्गमीटर जमीन को लेकर भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच विवाद है। यह जमीन 1994 में खरीदी गई थी। इस पर कोर्ट ने रेस्ट दिया हुआ है। केंद्र सरकार जब नेपालगंज की ऐतिहासिक नेपाल लिमिटेड (पम) को बेचने की तैयारी कर रही है, तब मध्य प्रदेश सरकार ने उसकी 1199 एकड़ जमीन में से 527 एकड़ 'सरप्लस' भूमि पर अपना दावा ठोक दिया है। हालांकि राज्य सरकार अपनी सम्पत्तियां पहली बार नहीं बेच रही है। विगत पांच सालों में राज्य सरकार की 170 प्रॉपर्टियां बेची जा चुकी हैं और इनके माध्यम से 110.88 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। हालांकि राज्य सरकार पर लिखना कर्ज है, उसकी तुलना में यह राशि कि ऊँच के मुह में जॉरे के बराबर ही है। अलबत्ता मप्र सरकार का दावा है कि उसने राज्य सरकार से सरप्लस है, इसलिए कर्ज लेने की उसकी पात्रता बनी हुई है।



अ रावली आड़ी पर्वतमाला है। भारत की ज्यादातर पर्वत मालाएं मानसून के अनुकूल उत्तर से पूर्व होती हैं। अरावली इनके विपरीत पश्चिम से उत्तर-मध्य की तरफ खड़ी

हा यह पक्षमन से आने वाली वायु के साथ रसीली हवाओं को अपने जालों में समा लेता है। इसीलिए इसे भारत की रीढ़ कहते हैं। यह अकेली पर्वतमाला है, जिसमें पुरानी पर्वत चोटियों के बीचों-बीच नए रेत के टीले दिखाई देते हैं। 'बिरला साइंस इंस्टीट्यूट, जयपुर' के निदेशक प्रो. एमएस डावरिया ने 'रिमोट सेंसिंग' द्वारा अध्ययन करके, उच्चतम न्यायालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन न्यायमूर्ति एमएन ग्रेचेचेलैया ने भारत सरकार को इन रेतली हवाओं से दिल्ली को बचाने का निर्देश दिया था। तभी 7 मई 1992 'आरवाली संरक्षण नोटिफिकेशन' भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय पर प्रकाशित किया था।

इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय ने अरावली को एक समग्र पर्वतमाला मानकर बचाना तय कर दिया था। तब लगता था कि अरावली के आसू न्यायालय ने पोंडू दिए हैं और अरावली के दर्द को न्यायपालिका ने समझ लिया है, लेकिन अब 20 नवंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय, रिपोर्ट और शपथपत्र को पढ़कर लगता है कि ऊंच - नीच में पहाड़ को भी बांट दिया गया है। 100 मीटर से अधिक ऊंची पहाड़ियाँ ही अरावली है, इससे नीचे अरावली नहीं है। उन पहाड़ियों को खोजकर निकालो जिन्को हमने 1980 के दशक से बचाने की मुहिम खड़ी की थी।

अरवलौ के पुनर्जीवन हेतु वर्ष 1986 में गोपालपुर गांव में मेवालों का बांध बनाकर, पहाड़ियों पर पशुओं की चराई के दबाकों का काम करने का काम शुरू किया था। इस बांध के तैयार होने से गोपालपुरा गांव में पानी आ गया था। गांव से लाचार, बेकार, बीमार होकर उड़ते युवक शहर चले गए थे, लेकिन कुओं में पानी आते ही शहर से वापस गांव आने लगे थे। तभी उसके रिश्तेदार पालपुर के जंसी मीणा ने गोपालपुर आकर कहा था

अरावली के पुनर्जीवन हेतु वर्ष 1986 में गोपालपुर गांव में मेवालों का बांध बनाकर, पहाड़ियों पर पशुओं की चराई के दबाव को कम करने का काम शुरू किया था। इस बांध के तैयार होने से गोपालपुरा गांव में पानी आ गया था। गांव से लाचार, बेकार, बीमार होकर उजड़े युवक शहर चले गए थे, लेकिन कुओं में पानी आते ही शहर से वापस गांव आने लगे थे। तभी उनके रिश्तेदार पालपुर के जंसी मीणा ने गोपालपुरा आकर कहा था कि हमारे सभी कुएं खदानों के कारण सूख गए हैं, वहां जल-संरक्षण हेतु जोहड़ की जरूरत है। तभी पालपुर में जंसी मीणा, तिलवाड़ी के छोटेलाल मीणा के यहां जोहड़ बनाने का काम किया था। छोटेलाल मीणा कहते थे कि खनन से पहाड़ तो उजाड़ ही रहा है; इससे हम भी उजड़ रहे हैं। हमारे लिए जो जोहड़ बना है, उससे हम तभी बसे रह सकते हैं, जब खनन बंद होगा।

कि हमारे सभी कुएं खदानों के कारण सूख गए हैं, जहाँ जल-संरक्षण हेतु जोहड़ की जरूरत है। तभी पालपुर में जांसी मीणा, तिलवाड़ी के छोटेला ल मीणा के यहाँ जोहड़ बनाने का काम किया था। छोटेला ल मीणा कहते थे कि खनन से पहाड़ तो उजाड़ ही रहा है; इससे हम भी उजाड़ रहे हैं। हमारे लिए जो जोहड़ बना है, उससे हम तभी बसे रह सकते हैं, जब खनन बंद होगा।

'तरुण भारत संध' ने दोनों गांव में जोड़ड़ बनाए, लेकिन इनका सारा पानी खदानों में चला गया क्योंकि कुओं से ज्यादा गहरी खदानें थीं। तभी से पानी के लिए ही खदानों के विरुद्ध लड़ाई शुरू हुई। उच्चतम न्यायालय के आदेश से जैसे ही खदानें बंद कराई गईं तो उनके दोनों कुओं में पानी आ गया। फिर तो जैसी का बेटा ख्याली मीणा, महेश शर्मा, गोपी कुम्हार मलाना ने मिलकर पूरी 'अरावली बचाओ यात्रा' की। यैसे पालपुर, तिलवाड़ी, तिलवाड़, बैरवा डूंगरी, बलदेवागढ़, गोवर्धनपुरा, मझना के पांचू सरपंच ने प्रत्यक्ष सत्याग्रह करके खनन रोकवाया था। मल्लान में पाटनी, आरके मार्बल जैसे बड़े - बड़े खान मल्लान पहुंच गए थे। वे भी लोक सत्याग्रह के कारण वहां खान नहीं चला सके थे। तब उच्चतम न्यायालय ने पर्वतमाला और उसमें रहने वाले लोगों से अरावली का दर्द सुनकर उसे बचाने दिया था।

उच्चतम न्यायालय को उस आदेश ने अरावली पर्वतमाला की जान और इज्जत बचाई थी। मेरे विरुद्ध भयानक मुकदमे खान मालिकों ने दर्ज किए थे। पुलिस भी अपनी कार्रवाई करने लगी थी। पर्यावरण कार्यकर्ता को बचाने हेतु सरकार ने उसी काल में कानून में बना दिया था और उस कानून का

पालन भी होता था। तब पहाड़ का दर्द सुना जाता था। पहाड़ और पहाड़ बचाने वालों को न्यायालय बचाता था। अब क्या नया हुआ मालूम नहीं? अरावली पर्वत की पीड़ा तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। जो अरावली की पीड़ा जानते हैं, वो अरावली को बचाना चाहते हैं, लेकिन अरावली को



बचाने से, बचाने वालों की पीड़ा बढ़ने लगी है।
 अरावली तो लोगों का थपने जंगलों की पीड़ा
 कम करने के लिए आधा पर्वत बनकर खड़ा है।
 इसलिए राजस्थान के रंगिस्तान से अधिक अच्छी
 वर्षा अरावली क्षेत्र में होती है। अरावली पर्वतमाला
 में 'सीधी साझ' (सीधी दरार) हैं, इनके द्वारा वर्षा
 जल अरावली के भूजल भंडारों में जमा होता रहता
 है। इसी से चारों राज्य में जहां अरावली पर्वतमाला
 है, वहां मीठा जल, सुरक्षित पेयजल आज भी
 उपलब्ध होता रहता है। यह पर्वतमाला 'भूजल बैंक'
 को समृद्ध बनाकर रखती है। इसलिए दिल्ली के
 खंडावाप्रस्थ, हरियाणा के काला पहाड़, गुडगांव,
 फरीदाबाद, नूह को भू-जल संरक्षित घोषित करने के

बात चली थी। हरियाणा में जहां पहाड़ियां हैं, वहां मीठा पेयजल, स्वस्थ जल उपलब्ध है। शेष क्षेत्रों में खारा जल है।

ऐसा ही अरावली क्षेत्र के चारों राज्यों में आज भी देखने को मिल रहा है। यदि अरावली पहाड़ियों में खन कर दिया तो बालू की कांस्तुन बिगड़ जाएगा। बेमौसम वर्षा चक्र चलेगा, उसके कारण बाढ़ - सुखाड़ की मार पड़ेगी, खेती का उत्पादन घटेगा, खाद्य व पेयजल सुरक्षा पर संकट बढ़ेगा। इस कारण लोगों में बेवैनी बढ़ रही है। अब अरावली में सतत विकास के नाम पर खनन निषाध करेगा। यदि हम अरावली की पीडा को समझें तो इस संकट को मिटाने की कोशिश आरंभ हो सकती है। यह सब स्वयं ही दृष्टिमान का काम करेगी और स्वस्थ जलवायु, खाद्य, जल-सुरक्षा प्रदान करेगी। हमारे गांवों को लाचारी, बेकारी, बीमारी से मुक्त दिलाती रहेगी। यही अरावली क्षेत्र के प्रदूषण, पर्यावरण शोषण, अतिक्रमण मुक्त रखने के रास्ते पर आगे बढ़ाएगी। खनन खुलते ही जंगल पर अतिक्रमण, जल-संसाधनों के प्रदूषण और युवाओं का शोषण शुरू होगा।

जंगल कटने से मिट्टी कटती और खेतों में गाद जमा होगी। मिट्टी के कटाव से खेतों की जमीन कम होगी। पशुओं के लिए चारा, महिलाओं के लिए पेयजल संकट बढ़ेगा। जब खदान चलती थी, तब लोग मालिक से मजदूर बन गए थे। गांव छोड़कर लोग उड़ने लगे थे। जब खदान बंद हुई तो वे अपनी जमीन ठीक करके, उसमें खेती करने लगे थे। अब फिर खदानें चालू होंगी तो पहले जैसी ही बढ़ाही शुरू होगी। अरावली के लोगों और अरावली का दद एक है। अरावली पर्वत की प्राकृतिक पीड़ा और मानवीय संस्कृति पर संकट एक साथ ही आ गया है। इसे रोकने के लिए हम संकट को समझें और अरावली के लोग संगठित होकर, खनन से अरावली को बचाए। खनन मुक्त अरावली का पर्यावरण सुरक्षा के साथ-साथ सतत रूप में पूरे भारत और दुनिया के लिए शुभ होगा। (सप्रेम)

वंदे मातरम् पर पीएम का वक्तव्य

प्रमोद भार्गव

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।



मुस्लिम तुष्टिकरण की बुनियाद पर भारत को जितनी नहीं उठानी पड़ी है, दुनिया के अन्य किसी देश ने नहीं उठाई। इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन से की, इसी कड़ी में वंदे मातरम् गीत का टुकड़े किए गए और फिर देश का भी बँटवारा जिन्ना की अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की जड़ के चलते हो गया। जबकि संपूर्ण वंदे मातरम् गीत भारत की शाश्वत संस्कृत्य है। राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में हुई चर्चा के दौरान गीत के विभाजन के लिए पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सीधे जिम्मेवार ठहराया। कहा, 'नेहरू ने जिन्ना की सांसाध्यिक चिंताएं दोहराकर वंदे मातरम् के साथ विश्वासघात किया। गीत के टुकड़े कराए। इससे देश तुष्टिकरण की राजनीती की राह पर चल पड़ा, जो देश विभाजन पर जाकर थमा।' इसी तुष्टि के चलते 1875 में रचित इस गीत के केवल दो पद राष्ट्रीय गीत के रूप अपनाए गए।

मोदी को इस कथन ने इतिहास के इस काले पन्ने पर जमा धूल को हटाने का काम नए सिरे से कर दिया है। जबकि आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम् की भावना पूरे राष्ट्र का जागरण किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में इस गीत के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। जिस भाव से वंदे मातरम् के टुकड़े किए गए थे, कालांतर में उसी भाव ने विभाजन के बीज बो दिए थे। जबकि यह ठोस और निर्विवाद सच्चाई है कि देश को आजादी दिलाने में इस गीत की अहम भूमिका रही है। बकिमचंद्र चटर्जी के बांग्लाभाषा में लिखे गए उपन्यास 'आनंद मठ' में यह गीत दर्ज

है। राष्ट्रगान के रूप में स्वीकारा गया यह गीत कोई मामूली गीत नहीं है। भारत को उसकी व्यापक राष्ट्रियता की पहचान और स्वाभिमान इसी गीत से प्राप्त हुए। नागरिक सभ्यता के विरासत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानव सेवा के मूल्यों के उत्स इसी गीत के समवेत स्वर की उपज है। अंग्रेजों के विरुद्ध भिन्न जातीय और धर्म-समुदायों को संगठित करने के अभियान में इसी गीत की भूमिका बुलंद थी। तय है, वंदे मातरम् क्रांति के स्वरो में नींव का पत्थर था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की रक्त धमनियों में विद्रोह की उग्र भावना इसी गीत की देन है। 1942 में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को देशव्यापी धरतल इसी गीत के बूते मिला था। और वह यही आंदोलन था, जिसमें गांधी ने 'करो या मरो' का नारा दिया था। यह नारा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत पर प्रश्नचिह्न खड़ा करने वाला भी माना जाता है। सुभाषचंद्र बोस की आजाद हिन्द फौज के फौजियों ने भी इसी गीत को गाते हुए मातृभूमि की बलिदेहि पर प्राण न्यौछावर किए थे। हालाँकि महात्मा गांधी 1905 में ही लिख चुके थे कि वंदे मातरम् इतना लोकप्रिय हो गया है कि वह राष्ट्रगान जैसा बन गया है।

14 अगस्त 1947 को मध्य-रात्रि में जब देश आजाद हो रहा था, तब इस मंत्र-गीत का गायन श्रीमती सुचेता कृपलानी ने किया और वहाँ उपस्थित लोग इस गीत के सम्मान में गीत खत्म न हो जाने तक खड़े रहे थे। 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता का सूर्योदय हो रहा था, तब आकाशवाणी पर पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने इसे बड़े

है रोचक ढंग से गाया। आखिरकार 24 अगस्त 1948 को जन-गण-मन के साथ इस गीत को भी राष्ट्र गीत की प्रतिष्ठा मिली। लेखक और दार्शनिक युगदूष होते हैं, इसलिए बाबू ने इस गीत को लिख जाने के वक्त ही अपनी निम्नलिखित दिव्य-दृष्टि से अनुभव कर लिया कि यह गीत राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनकर लोकप्रियता के शिखर चूमेगा,

अक्टूबर 1937 को लखनऊ में मोहम्मद अली जिन्ना ने देवेंद्र मातरम् का विरोध किया। वस्तुतः नेहरू ने इस विरोध के पांच दिन बाद ही सुभाष बोस लिखे एक पत्र में कहा कि 'आनन्द मठ में उल्लेखित वंदे मातरम् की प्रथमभूमि मुसलमानों को उकसा सकती है।' इसी के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी ने आचार्य नेन्द्रे देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसमें मौलाना आजाद, पंडित नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस जैसे प्रखर संसृति मर्मज्ञ सदस्य थे। समिति को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे रवीन्द्रनाथ ठाकुर से विचार-विमर्श कर वंदे मातरम् के संबंध में दो दृढ़ सलाह दें। समिति द्वारा रवीन्द्रनाथ से परामर्श के बाद जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, उसके उपरत कांग्रेस कार्यकारिणी ने फैसला लिया कि हरेक राष्ट्रीय सार्वजनिक सभा में वंदे मातरम् के केवल दो पद गाये जाएं। यानी कांग्रेस मुस्लिम लीग के समक्ष झुकी और मुस्लिम अधिकरण की राह पकड़ ली। तुरिष्ठ का यहि रास्तरा देश को विभाजन के द्वार तक ले गया।

बावजूद देश-विभाजन के लिए जिम्मेदार मुस्लिम लीग के नेता वहे मातरम को बुतपरसी, अर्थात् तातुसल्लाम, मूर्ति पूजा मानते हुए इसका विरोध लगाता करते रहे। इसका बहाने लीगीयों ने अपरस्पक्षकों को खूब उकसाया। नतीजतन १९३८ तक काँग्रेस के जो प्रमुख मुस्लिम नेता इस की नीति पर शरीय गरिमा का ख्याल रखते चले आ रहे थे, वे भी धीरे धीरे जुवान से इसका विरोध करने लगे। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बहुसंख्यक हिंदू और सिख हटपूर्वक इंग्लिश गीत की महिमा के बखान में लगे रहे। बाद में साझा

सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के नजरिये से उर्दू के उदारवादी कवियों व राजनीतिकों ने वंदे मातरम् का अनुवाद 'ऐ मादर, तुझे सलाम करता हूँ' किया, अर्थात् 'हे माता, तुझे प्रणाम करता हूँ' करके किया, लेकिन कट्टरपंथियों के भाव उतरा नहीं। जबकि मुल्क को गुलामी से आजाद कराने की इस इबादत में गलत कुछ भी नहीं था। अरबी-फारसी के अनेक कवियों ने भी देश को 'माँ' कहकर संबोधित किया है। लिहाजा राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाओं व उद्गारों को प्रचलित रूपकों अथवा प्रतीकों में प्रकट करना मूर्ति पूजा या बुतपरस्ती कतई नहीं थी। वंदे मातरम् एक मौलिक रचना है, इसकी व्याख्या धर्म नहीं, केवल साहित्य के संदर्भ में होनी चाहिये थी। इसे यदि कोई सांसद या विधायक इस्लाम विरोधी जताता है, तो उसका मकसद धर्म के बहाने राजनीतिक रेटियाँ संकेनार बाध, जो अलगाववादी राजनीति की संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक है। जिज्ञा और अन्य लीगी इसी विभाजनकारी मानसिकता से काम करते रहे और देश दो टुकड़ों में बंट गया। स्वतंत्र भारत में निर्वाचित मुल्क मुसलिम सांसद और विधायक संविधान की शपथ लेने के बाद भी सांसद में इस गीत का अनादर करते रहते हैं। ऐसे ही चंद सिरफिरे मुस्लिमों ने आजाद हिंद फौज के नारे, 'जय हिंद' का भी विरोध किया था। दैनिक अखबार 'डान' ने वंदे मातरम् की आलोचना की थी, तब गंधी जी को कष्टान पड़ा था, 'वंदे मातरम् कोई धार्मिक नारा नहीं है, यह विशुद्ध राजनीतिक नारा है।' यही नारा था, जिसमें सोये हुए भारत को जगाने का काम करके, आजादी हासिल कराई थी।अतएव संसद में इस गीत के लेना चाहिए जिससे बहस में देश की संप्रभुता एवं अखंडता से खिलवाड़ की गुंजाइश ही नहीं रह जाए?

तुष्टिकरण की नींव बनी वंदे मातरम् का विभाजन

स्वामी, सुबह सवेंरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जेन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोक्लि
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विचारों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHINI/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subhassavernews@gmail.com

‘सुबह सवेरे’ में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं।
इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

समं कोई दो मत नहीं कि वे बड़े व्यक्ति हैं। वे काफी बड़े व्यक्ति हैं जिनके आगे बाकी सब छोटे छोटे दिखाई देते हैं। जैसे सूर्य और खड्डो। बड़े व्यक्ति होने के कारण पूरे क्षेत्र में भाईसाहब के नाम से जाने जाते हैं। भाईसाहब अच्छे लेखक हैं। वैसे वे लेखक कम हैं। बाकी ज्यादा हैं। उनका अपना व्यवसाय है। तो व्यवसायी भी है। व्यवसायी है, इसलिए धनाध्य भी हैं। धनाध्य हैं, इसलिए बाकी सारे सुभोते उनके पास हैं। सुभोते हैं, तो कई लोग उनका आसपास मंडरते रहते हैं। उनको पैसे पुरतों के पास भँवै और तितलियाँ मंडरती हैं। उनकी भी आम आदमी जैसी तामा इच्छाएँ हैं। परंतु आम इच्छाएँ, उनकी इच्छाएँ नहीं हैं। धनाध्य आदमी, अपने-आपको ज्ञानाध्य दिखाने का प्रयत्न भी करते तो कोई आश्चर्य नहीं। लक्ष्मी का प्रयत्न लक्ष्मी को अपनी बांदी समझने का हमेशा रह है। कहते हैं, लक्ष्मी उलू की सवारी करती है। पर सरस्वती को इस बात का दंभ है कि वह ज्ञान की देवी है और लक्ष्मी की उपस्थिति उसी से है। और भाईसाहब को देखकर लगता है कि जो दंभी होते हैं उनका पर खाली होता है। मजे की बात यह है कि ज्ञानाध्य होकर वे व्यक्ति नहीं रह जाते, व्यक्तित्व हो जाते हैं। वैसे यह भी सही है कि हर धनाध्य भी एक व्यक्तित्व होता है वैसे ही एक कुल और भी व्यक्ति से व्यक्तित्व हो जाते हैं। यहाँ वे परदहारी होते हैं, नेता होते हैं या कुल न होते हैं, तब भी कुल तो होता है कि वे व्यक्तित्व हो जाते हैं। वे चिंतक

हो सकते हैं। आलोचक हो सकते हैं। वे समाजसेवी हो सकते हैं। वस्तुतः इन दिनों व्यक्तित्व हर जगह हावी हैं। ऐसे में भाईसाहब व्यक्ति होने के साथ व्यक्तित्व भी हैं। उनके मन में एक इच्छा लेखक बनने की है। लेखक हो जाना बुद्धिमान होने की गारंटी है या निशानी है। ऐसा वे



व्यक्तित्व का टोटा नहीं है, पर व्यक्तित्व के लिए लेखक होना, चौथे चांद के समान है। तो वे लेखक भी हैं। लेखक हैं तो लिखते भी हैं। लिखते हैं, इसलिए लेखक हैं; यह आप कह सकते हैं। लेखक नाम ही लिखने वाले का है, यह अलग से बताने की बात नहीं है। तो लिखने

के लिए वे क्या लिखते हैं, यह उन्हें तय नहीं करना पड़ता। अभी कल ही उन्होंने कुछ लिखा और दस दिनी से उसे एक पत्रिका को प्रेषित भी कर दिया। वैसे ये ऐसा हमेशा से करते हैं। इस तरह उनकी लेखकीय उम्र इतनी हो गई है कि उसे वे अपनी हर रचना छपने की गारंटी मान कर चलते हैं। कुछ हैं जो उनकी रचनाएँ बिना पढ़े छाप भी दें, पर सब संपादक एक से नहीं होते। वे नाम पढ़कर नहीं बल्कि रचना पढ़कर रचना के छापने का निर्णय करते हैं। यह निर्णय, भाईसाहब को, स्वाभाविक है, नागवार गुजरता है। और फिर उस पर संपादक यह टीप लिख दे कि रचना कुछ कमजोर है। उनके अहं को ठेस पहुँचती है। वे रचना के समर्थन में तर्क भी देते हैं। विज्ञापन भी। विज्ञापन से पत्र चलता है। पत्र के चलने से रचना

अभी यही हुआ। एक रचना उन्होंने एक साहित्यिक पत्रिका को भेज दी। शायद जितनी बड़ी रचना नहीं थी, उससे बड़ा उनका परिचय था। यह परिचय यह दर्शाने के लिए था कि वे वाकई बड़े लेखक हैं। जिसमें साठ सत्तर किताबों के साथ जाने अनजाने तीन सौ साठ पुरस्कारों की

लेखनी सूची थी। चार से बीस बैठकों, संगोष्ठियों और कवि सम्मेलनों में अथक्षता, मौखीयता और विशिष्टातिथ्य का पद सुशोभित करने का गौरव उन्हें प्राप्त था। ये बात अलग कवि के अधिकांश गीतों का व्युत्पत्ति उन्होंने ही वहन किया हुआ था। आखिर बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे छोटे जोहम उठाने ही पड़ते हैं। इस बार कुछ हो न हो लेखकों को उनकी इसी इच्छा ने इतना सर उठाया कि उन्होंने पत्रिका को हर माह विज्ञापन इस शर्त पर देना स्वीकार किया कि उनकी रचनाओं पर संपादक स्वयं टीप लिख कर उसे छापें। पत्रिकाओं की स्थिति क्या है, यह न पत्रिकाओं से छिपी है, न लेखकों से, न मालिक से, न संपादक से। अब ऐसे में घोड़े को अगर जिंदा रखना है तो घास चाहिए, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? यंत्रिका निकले, निकलती रहे, इससे बड़ी कामना किसी को हो सकती है। तो प्रस्ताव स्वीकार हो गया।

उन्के गरीब खाने पर कवि लेखकों का आना जाना चलना रहता है। जो उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा भी करते हैं। सैदे से भी पुराने जमाने से ये चलन है कि राजे- महाराजे, साहूकार- साहूकार अपने शौक की खातिर कहे जा अपनी प्रशंसा के लिए या बड़पन दिखाने के लिए कुछ कवियों को आमंत्रित कर ही लेते थे। सारे ही कुंभनदस की तरह जगल नहीं होते थे। जो हरिनाम बिसर जाएंगे और आने वाले में चम्पल घिस जाएंगी इस डर से राज दरबार जाते ही नहीं थे।

स्वास्थ्य सेवाओं के व्यावसायीकरण के खिलाफ चलेगा राष्ट्रीय अभियान

रायपुर। पूरे भारत से 19 से ज्यादा राज्यों के लगभग 350 प्रमुख स्वास्थ्य नेतृत्वकर्ता, एक्टिविस्ट्स, जनांदोलनों और समुदाय के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ रायपुर, छत्तीसगढ़ में दो दिवसीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दिनोदिन गंभीर होती जा रही कठिन स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के साथ-साथ आम जनता के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था में नीतिगत बदलावों की मांग और जमीनी स्तर पर जन स्वास्थ्य आंदोलन को रणनीतिक रूप से मजबूत करना था। सम्मेलन की शुरुआत में स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की मौजूदा प्राथमिकताओं और निजीकरण के बढ़ते खतरे की तरफ ध्यान दिलाते हुए जन स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए ठोस पहलकदमी पर जोर दिया गया। हाल ही में नीति आयोग के एक स्कूलर को लेकर खास चिंता जताई गई, जिसमें जिला अस्पतालों के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल को बढ़ावा दिया गया है। प्रतिभागियों ने चिंता जताई कि इससे देश की सबसे कमजोर और जरूरतमंद आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुँच मुश्किल हो जाएगी।

मुख्य वक्ता कम्युनिटी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉ. रितु प्रिया ने नज़रिए में बड़े बदलाव की मांग की। उन्होंने कहा, 'बहुत



लंबे समय से, स्वास्थ्य के बारे में हमारी समझ सिर्फ डॉक्टरों और अस्पतालों तक ही सीमित रही है।' 'हमें समुदाय के तरीकों, पारंपरिक ज्ञान और हमारी आधी आबादी की सेवा करने वाले इनफॉर्मल डॉक्टरों की ताकत को वैलिडेट और इंटीग्रेट करना होगा। एक सच्चा स्वस्थ समाज ज़मीन से

बनता है, ऊपर से नीचे थोपा नहीं जाता।'।

ग्रीन नोबेल अवार्डी प्रफुल्ल सामंते ने कहा, 'हमारी सरकार का मौजूदा रास्ता सिर्फ जनविरोधी नीतियों का निर्माण नहीं है; यह उस सवैधानिक ताने-बाने पर हमला है जो बराबरी और समावेशी मूल्यों का वादा करता है। वे

सुनियोजित तरीके से निजी लाभों के लिए जन स्वास्थ्य का व्यापार कर रहे हैं, और आरुपणन कार्ड जैसी पॉलिसी मरीजों से ज्यादा कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने में काम आ रही है।'

सम्मेलन में तय किया गया कि व्यावसायिक और

पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर एक पखवाड़ा अप्रैल, 2026 में मनाया जाएगा। व्यावसायिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर एक राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के खिलाफ और सार्वजनिक स्वास्थ्य की मजबूती के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाया जाएगा। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य के विभिन्न मुद्दों पर आधारित एक सात दिवसीय कोर्स की शुरुआत मार्च, 2026 तक होगी। देश के 100 जिलों में मजबूत स्वास्थ्य कार्यकर्ता तैयार करेंगे। महिला हिंसा और महिला स्वास्थ्य तथा वंचित समुदायों के स्वास्थ्य के मुद्दों पर पृथक समूह का निर्माण होगा।

सम्मेलन के अंत में सभी प्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयासों से तैयार जन स्वास्थ्य घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें जन स्वास्थ्य के मुद्दों का समर्थन करते हुए जमीनी और राष्ट्रीय स्तर पर सार्वहिक प्रयास करने और सक्रिय गोलबंदी का संकल्प लिया गया। सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में विषय विशेषज्ञों अमितावा गृह, ऋतु प्रिया, डॉ. सुनीलम, प्रफुल्ल सामंतेरा, कैलाश मीन, राजकुमार सिन्हा एवं समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ ही पीडित और प्रभावित दिनेश रायसिंग, चुन्नी जी आदि ने विभिन्न सत्रों में अपने-अपने अनुभव साझा किए।

संक्षिप्त समाचार

दुग्ध समृद्धि सम्पर्क अभियान के तहत कलेक्टर श्री विश्वकर्मा की उपस्थिति में प्रशिक्षण सम्पन्न



रायसेन (निप्र)। रायसेन स्थित शासकीय पशु चिकित्सा एवं डेयरी विकास कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में दुग्ध समृद्धि सम्पर्क अभियान के तहत जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसमें कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने पशु चिकित्सकों, सहायक पशु चिकित्सकों तथा गो-मित्रों से कहा कि जिले में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि पशुपालकों को पशु स्वास्थ्य, अधिक दुध देने वाली गाय-भैंस की जानकारी, उनके पोषण और टीकाकरण आदि की समुचित जानकारी हो। इसके लिए सभी आज यहां दिए जा रहे प्रशिक्षण को पूरी गंभीरता से प्राप्त करें तथा कोई संशय या जिज्ञासा हो तो उसका समाधान प्राप्त करें। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत सभी गांवों में जाकर पशुपालकों से गृह बैठ करंगे तथा उन्हें पशु स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के उपायों के बारे में जानकारी देंगे। प्रशिक्षण का उद्देश्य पशुपालकों तक उन्नत नस्ल, पोषक आहार आदि के साथ ही नवीनतम जानकारी और सेवाएं पहुंचाकर उनकी आय को दोगुना करना है। प्रशिक्षण में उप संचालक श्री शुक्ला द्वारा पशुओं की देखरेख, उनके स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु पशुओं को दिए जाने वाले पोषण आहार आदि के बारे में विस्तार से बताया गया।

सोहागपुर विधायक की अनुशंसा पर 01 निर्माण कार्य हेतु 05 लाख 80 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी

नर्मदापुरम (निप्र)। सोहागपुर विधायक श्री विजय पाल सिंह को अनुशंसा पर कलेक्टर श्री सीनिया मीना द्वारा विधायक निधि से जनपद पंचायत माखननगर में 01 निर्माण कार्य के लिए 05 लाख 80 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। जिला योजना एवं संस्थिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोहागपुर विधायक श्री विजय पाल सिंह की अनुशंसा पर विधायक निधि से म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ भंडारण केन्द्र माखन नगर में किसान विश्राम शेड निर्माण के लिए 05 लाख 80 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

सुपर सीडर मशीन से की गई 25 बीघा क्षेत्र में बोनी, कृषक श्री राजेंद्र सिंह यादव हुए लाभान्वित



विदिशा (निप्र)। जिले में आधुनिक कृषि साधनों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिरोंजा विकासखंड के ग्राम कुडका के कृषक श्री राजेंद्र सिंह यादव द्वारा सुपर सीडर मशीन अनुदान पर ली गई है। कृषक द्वारा सुपर सीडर मशीन से स्वयं की 20 से 25 बीघा में बोनी की गई है। कृषक श्री यादव ने कृषि विभाग की अनुदान (सब्सिडी) योजना के अंतर्गत सुपर सीडर मशीन प्राप्त की है, जिसके उपयोग से उन्होंने अपने खेतों में लगभग 25 बीघा क्षेत्र में सफलतापूर्वक बोनी का कार्य पूर्ण कर लिया। सुपर सीडर मशीन से की गई बोनी से भूमि की नमी संरक्षित रहती है, अवशेष प्रबंधन बेहतर होता है तथा कम समय में व्यापक क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण बुवाई संभव हो पाती है। इससे फसल उत्पादन में वृद्धि और लागत में कमी की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती हैं। कृषक श्री यादव ने बताया कि मशीन से कार्य तेज, किफायती और अधिक वैज्ञानिक तरीके से संपन्न हुआ है, जिससे रबी फसलों की समय पर बोनी सुनिश्चित हो सकी। कृषि विभाग द्वारा आधुनिक तकनीक आधारित उपकरणों के प्रति किसानों को प्रोत्साहित करने की लगातार पहल की जा रही है। जो कृषकों के लिए लाभप्रद सिद्ध हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता वृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

परीक्षा के दृष्टिगत मकान गणना और जनगणना की अवधि तय करें : सचिव श्री जैन

भारत की जनगणना 2027 : मुख्य सचिव श्री जैन ने राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक ली

भोपाल। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने सभी विभाग अध्यक्षों को निर्देश दिये है कि आगामी जनगणना 2027 के दृष्टिगत प्रशासनिक इकाइयों में जो भी परिवर्तन किये जाने हैं वे 31 दिसम्बर 2025 तक अनिवार्यतः कर लिये जाए। मुख्य सचिव श्री जैन की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में भारत की जनगणना 2027 के दृष्टिगत राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। उल्लेखनीय है कि जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 01 अप्रैल से 30 सितम्बर 2026 के दौरान 30 दिवस की अवधि में किया जायेगा। मुख्य सचिव ने सम्बन्धित विभागों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि स्कूली बच्चों की पढ़ाई, मानसून इत्यादि को ध्यान में रखते हुए उक्त 30 दिवस की अवधि निर्धारित की जायें।

बैठक में बताया गया कि जनगणना के द्वितीय चरण में जनसंख्या की गणना का कार्य पूरे देश में एक साथ फरवरी 2027 में किया जायेगा। मुख्य सचिव श्री जैन ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया कि वे जनगणना के द्वितीय चरण को ध्यान में रखकर वर्ष 2026-27 का शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करें। उन्होंने परीक्षाओं की समय-सारणी इस तरह तैयार करने के निर्देश दिये है जिससे विद्यार्थियों को कोई

असुविधा नहीं हो। साथ ही सम्बन्धित विभागों को यह भी निर्देश दिये गये कि वे आपस में समन्वय करते हुए जनगणना 2027 के लिए मानव संसाधन की उपलब्धता के लिए योजना तैयार करें जिससे जनगणना का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

मुख्य सचिव श्री जैन ने आगामी जनगणना डिजिटल होने के मद्देनजर सर्वसम्बन्धितों को उचित

समय पर युक्तियुक्त प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। श्री जैन ने जनगणना के दौरान स्व-गणना (Self-Enumeration) किये जाने के प्रावधान की सराहना की। उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागों को यह भी निर्देश दिये कि वे जनगणना 2027 के कार्य के समन्वय के लिए अपने अपने विभागों में एक नोडल अधिकारी नामित करें। जनसंपर्क विभाग को जन सामान्य में जनगणना के प्रति जागरूकता लाने एवं भ्रातियों को दूर करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिये गये।

मुख्य सचिव श्री जैन ने स्पष्ट रूप से कहा कि आम जन को यह बताया जाना आवश्यक होगा कि जनगणना 2027 पहली बार देश में डिजिटल होगी,

जिसमें मोबाईल एप के माध्यम से आंकड़ों का संकलन एवं वेब पोर्टल के माध्यम से मैनेजमेंट एवं मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बात का प्रचार होना चाहिए कि जनगणना अधिनियम की धारा 15 के तहत जनगणना में संकलित व्यक्तिगत जानकारीयों गोपनीय होती है साथ ही इन्हें कहीं पर भी साक्ष्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

राज्य-स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (SLCCC) की इस पहली बैठक में अपर मुख्य सचिव, गृह, अपर मुख्य सचिव, सामान्य

प्रशासन, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास, सचिव, गृह एवं राज्य नोडल अधिकारी (जनगणना), निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय मध्यप्रदेश, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव, गृह श्री शिव शेखर शुक्ल ने बताया कि मध्यप्रदेश में गृह विभाग जनगणना के लिए नोडल विभाग है जो भारत सरकार, जनगणना निदेशालय एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के

मध्य समन्वय स्थापित करते हुए जनगणना सम्पादन में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। प्रारंभ में निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जनगणना 2027 की रूपरेखा, प्रारम्भिक तैयारियां, डिजिटल रोडमैप और संगठनात्मक ढांचा इत्यादि के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया। उन्होंने यह बताया कि इस बार की जनगणना में स्व-गणना (Self-Enumeration) का प्रावधान भी किया जायेगा जिससे कि आम नागरिक अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे।

निदेशक, जनगणना द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय महत्त्व के इस वृहद कार्य में लगभग 1 लाख 75 हजार प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक अमले की भी आवश्यकता होगी। निदेशक जनगणना द्वारा अवगत कराया गया कि जनगणना के प्रथम चरण के पूर्व परीक्षण का कार्य प्रदेश में जिला रतलाम की रतलाम तहसील, जिला सिवनी की कुई तहसील के कुछ चयनित ग्रामों में तथा ग्वालियर जिले के नगर निगम ग्वालियर के चयनित वार्डों में नवम्बर 2025 में कराया गया। पूर्व परीक्षण कार्य को राज्य शासन एवं सम्बन्धित जिला प्रशासन के सहयोग से सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है।

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के अंतिम निराकरण में तेजी लाने के कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने दिए निर्देश



टीएल बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने की सीएम हेल्पलाइन तथा विभागीय कार्यों की समीक्षा

रायसेन (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा द्वारा विभागीय योजनाओं, गतिविधियों तथा सीएम हेल्पलाइन की विभागवार विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा द्वारा मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण एसआईआर अंतर्गत शेष गणना पत्रकों को शीघ्र डिजिटाइज्ड करने के निर्देश संबंधित एसडीएम को दिए। उन्होंने विभागवार सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से

अंतिम निराकरण किया जाए। जिला अधिकारी स्वयं व्यक्तिगत रूप से निराकरण कराएं तथा संबंधित व्यक्ति से चर्चा भी करें। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि राजस्व विभाग की सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की गति धीमी है, सभी एसडीएम और तहसीलदार शिकायतों के निराकरण में तेजी लाएं।

इसी प्रकार वन विभाग की प्रदेश में 45वीं रैंक होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने वन विभाग के अधिकारियों को आगामी सात दिवस में अधिक से अधिक शिकायतों का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने 50 दिवस और 100 दिवस से अधिक समयावधि वाली शिकायतों का भी अंतिम निराकरण कराने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा के दौरान जबाबदावा दर्ज किए बिना शिकायतें अगले स्तर

पर प्रेषित होने पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही शिकायतें लेबल जम्प वाले विभाग ऊर्जा विभाग, कृषि उपज मण्डी, खनिज साधन विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग, सेम ग्लोबल विश्वविद्यालय रायसेन, महिला बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, लोक स्वास्थ्य, बैंकिंग तथा स्कूल शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा द्वारा बैठक में जैविक प्राकृतिक खेती के कलस्टर विकसित किए जाने तथा जैविक उत्पादों के विक्रय हेतु केन्द्र के बारे में उप संचालक कृषि श्री केपी भागत से जानकारी लेते हुए कहा कि अधिक से अधिक किसानों को जैविक खेती से जोड़ा जाए। साथ ही जैविक उत्पादों के विक्रय हेतु सभी निकायों में बाजार भी उपलब्ध कराएं।

उन्होंने सब्जी की खेती के कलस्टर, दुग्ध उत्पादन के कलस्टर, फूलों की खेती आदि के कलस्टर विकसित किए जाने के कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार सीएमएचओ से इट राइट कैम्पेन के तहत की जा रही गतिविधियों की जानकारी लेते हुए गंभीरता के साथ क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने शासकीय कार्यालयों के व्यवस्थीकरण तथा रिकार्ड संधारण की जानकारी लेते हुए सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि जिले के सभी एसडीएम कार्यालयों को आईएसओ सर्टिफाइड कराना है तथा इसके उपरांत तहसील कार्यालयों को आईएसओ सर्टिफाइड कराना है।



सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के उपलक्ष्य में अधिकारियों को ध्वज लगाया

विदिशा (निप्र)। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के ऐसे जवान जो देश की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के दौरान एवं प्राकृतिक आपदाओं में कर्तव्य पालन करते समय वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, उनका स्मरण करने, सम्मान देने तथा देश आम नागरिकों का अपने सैनिकों के प्रति एकजुटता प्रकट करने के लिए देश में प्रतिवर्ष 07 दिसम्बर का दिन सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उक्त दिवस को देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों के परिवारों के कल्याण, विधवा एवं विकलांगों की आर्थिक रूप से सहायता, प्रदान करने के लिए ध्वज वितरित कर धन राशि एकत्रित की जाती है। इस अवसर पर विदिशा जिला मुख्यालय पर 07 दिसम्बर से 13 दिसम्बर तक सशस्त्र सेना झण्डा सप्ताह के अन्तर्गत आज 08 दिसम्बर सोमवार को कलेक्ट्रेट के बेतवा

सभाकक्ष में अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर, जिला पंचायत सीईओ सहित अन्य अधिकारियों को ध्वज लगाया जाकर स्वेच्छिक दान राशि संग्रहित की गई। कलेक्ट्रेट के बेतवा सभाकक्ष में भोपाल जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल राजीव खत्री के निर्देशानुसार सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर विदिशा सैनिक कल्याण बोर्ड के डब्ल्यूओ सेवा निवृत्त श्री सूबेदार चंद्रभान सिंह, केप्टन श्री एसपी चतुर्वेदी, सूबेदार मेजर श्री संतोष श्रीवास्तव, हवलदार श्री रामनारायण मीणा, हवलदार श्री एचडी बैरागी, नायक श्री नरेंद्र शर्मा, नायक श्री रविंद्र यादव आदि पूर्व सैनिकों ने अधिकारियों को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर फ्लैग लगाकर झंडा दिवस की शुभकामनाएं दीं और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों, वीर नारियों के लिए के लिए राशि एकत्रित की।

कृषि विभाग प्रति सप्ताह जिले में एक दिन जैविक हाट बाजार लगाए : कमिश्नर कृष्ण गोपाल तिवारी

राजस्व संग्रहण करने वाले विभाग तथा निर्माणविभाग इस वित्तीय वर्ष में शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा करें कमिश्नर ने संभागीय समय सीमा की बैठक में दिए निर्देश

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी ने उपसंचालक कृषि श्री जे आर हेडाऊ को निर्देश दिए कि सप्ताह में एक दिन जिले के किसी भी स्थान पर जैविक हाट बाजार लगाना सुनिश्चित करें। जैविक हाट में जैविक उत्पादन एवं सामग्री भरपूर मात्रा में रहे और जैविक हाट का व्यापक प्रचार प्रसार कर लोगों को जैविक सामग्री एवं वस्तुएं खरीदने के लिए प्रेरित भी किया जाए। कमिश्नर ने राजस्व संग्रहण करने वाले खनिज विभाग, जिला आबकारी विभाग, जिला परिवहन विभाग, लोक शौचालय टेक्स विभाग को इस वित्तीय वर्ष में राजस्व संग्रहण के सभी लक्ष्य की शत प्रतिशत पूर्ति करने के निर्देश दिए, साथ ही उन्होंने निर्माण विभाग सेतु निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री सड़क निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग को अपने सभी निर्माण कार्य इस वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण करने के निर्देश दिए।

कमिश्नर ने बैंक आधारित विभाग जनजाति कार्य विभाग, उद्यानिकी विभाग, उद्योग विभाग, कृषि विभाग आदि विभागों को भी अपने लक्ष्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा की वे हितग्राहियों को विभिन्न



योजनाओं में बैंक ऋण की स्वीकृति प्राथमिकता से कराना सुनिश्चित करें और शासन द्वारा दिए गए लक्ष्य की शत प्रतिशत पूर्ति करना भी सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने बैठक में भावांतर योजना में प्राप्त भावांतर की राशि, मॉडल रेट के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए की जिले के धार्मिक क्षेत्र में गुलाब की खेती को बढ़ावा देने के लिए

उद्यानिकी विभाग विशेष कार्य योजना बनाकर कार्य संपादित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने एक बगिया मां के नाम कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा करते हुए हितग्राहियों की जानकारी ली। कमिश्नर ने डॉ भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के संबंध में समीक्षा करते हुए निर्देश दिए की जिले के सभी क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना देने के लिए विशेष

रणनीति बनाई जाए। बताया गया कि इस योजना के तहत दिए गए 10 लक्ष्य में से पांच लक्ष्य को पूरा कर स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया है। कमिश्नर ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि वह मत्स्य पालन में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने एवं मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के संबंध में किए गए कार्यों की जानकारी अगले सप्ताह देना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने कहा कि मत्स्य पालकों को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाए ताकि उनके रोजगार में बढ़ोतरी हो सके और वह मत्स्य पालन से लाभ कमा सकें। कमिश्नर श्री तिवारी ने कलेक्ट्रेट्स एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह जिला स्वास्थ्य समिति की नियमित बैठक आयोजित ले तत् संबंध में उन्होंने संयुक्त संचालक स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि वह नियमित बैठकों की प्रोसिडिंग से उन्हें अवगत कराए। कमिश्नर श्री तिवारी ने हार्ड रिसर्क गंभर्वती महिलाओं एवं शिशुओं की देखरेख तथा कुपोषित बच्चों की चिन्हाकन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए, साथ ही निर्देश दिए की कलेक्टर एवं अधिकारीगण समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस

अधिकारों के साथ ही कर्तव्य बोध भी आवश्यक पूरक हैं अधिकार और कर्तव्य: विधानसभा अध्यक्ष



‘महिला सशक्तिकरण एवं मानवाधिकार’ विषय पर हुआ मंथन

भोपाल (नप्र)। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकारों के लिए कानून बनाये गये हैं, उन्हें लिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है, किंतु कर्तव्यों का बोध करना और कराना पड़ता है। जब हम अधिकारों के प्रति जागरूकता प्रदर्शित करते हैं तो कर्तव्य पालन का भी ध्यान रखना आवश्यक है। विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने यह बात अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर ‘महिला सशक्तिकरण एवं मानवाधिकार’ विषय पर आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कही।

विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने कहा कि महिला सशक्तिकरण प्राचीनकाल से ही हमारे संस्कारों में शामिल रहा है। हमारी संस्कृति में महिलाओं का स्थान सर्वोपरि रहा है। प्राचीनकाल से ही हमारी मातृ-शक्ति साहस, युद्ध-कौशल, तपस्या, त्याग और विद्वता से संपन्न रही है। उन्होंने कहा कि

महिला संरक्षण और सशक्तिकरण के लिये प्रावधानों के साथ ही उनके प्रभावी क्रियान्वयन का ध्यान रखना भी आवश्यक है। हमारे समाज में महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के भाव सदैव मौजूद रहे हैं। हमें पारंपरिक संस्कार और मान्यताओं में आई विकृतियों के प्रति सजग रहते हुए उनके निवारण के प्रयास तो करने ही चाहिये साथ ही उसके मूल सुजनात्मक स्वरूप और उपलब्धियों पर गर्व भी करना चाहिये।

विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी समाज की छोटी-छोटी कमजोरियों के प्रति सजग और संवेदनशील हैं। उनके कुशल नेतृत्व में आज देश की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों में 14 लाख महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुई हैं। इसके साथ ही सरपंच से सांसद तक हमारी निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या अधिक है। देश में 10 करोड़ बहनें 9 लाख स्व-सहायता समूहों के साथ जुड़कर उद्यमिता से समाज सेवा तक महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। कोविड काल में ‘आशा’ कार्यकर्ताओं का योगदान इसका अतुलनीय उदाहरण है।

विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रयासों से मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिये अभूतपूर्व प्रयास हुए हैं और उनके परिणाम भी अच्छे आये हैं। उन्होंने प्रदेश के अभिभावकों को भी धन्यवाद दिया, जिनके प्रयासों से और संस्कारों से देश की बेटियाँ पुलिस, सैनिक एवं अर्ध-सैनिक बलों में, उद्यमिता एवं व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन खेल समेत शैक्षणिक आदि सभी क्षेत्रों में देश प्रदेश का परचम लहरा रही हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि महिलाओं के मानवाधिकार और सशक्तिकरण सरकारों की संवैधानिक और समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के विजन को अमल में ला रहे मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मार्गदर्शन में राज्य सरकार महिलाओं की समस्याओं और उनके सशक्तिकरण के प्रति सजग और संवेदनशील हैं। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पूर्णतः ऑनलाइन पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू की है। हाल ही में 19 हजार से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की पूर्णतः पारदर्शी

ऑनलाइन भर्ती कर इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि हमारी केंद्र व राज्य सरकारों महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति सजग और सक्रिय हैं और हमारे प्रयास एवं योजनायें उसका आधार बने हैं। मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि वह आदिवासी समाज से हैं और समाज की महिलाओं की परेशानियां समझती हैं, इसलिये उनके निवारण के प्रति संवेदनशील हैं। उन्होंने परिवारों को भी इसके प्रति सजग रहते हुए बेटियों के साथ ही बेटों को भी बचपन से ही महिलाओं की रक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के संस्कार देने होंगे।

मानवाधिकार आयोग के सदस्य डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने कहा कि देश में महिला सशक्तिकरण के साथ ही मानवाधिकारों के सुधार की दिशा में केंद्र व राज्य सरकारें सजग हैं और समन्वित प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति सभ्यता के उदय के साथ इसके प्रति संजन और संवेदनशील है।

यूनन वूमन की स्टेट हैड सुश्री रे ने पारंपरिक रूप से घर, सार्वजनिक स्थलों के साथ ही आधुनिक डिजिटल स्पेस में भी महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण की आवश्यकता बताई।

आयोजन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण योजनाओं के प्रेजेन्टेशन दिया गया। प्रेजेन्टेशन में लाइली-बहना और लाइली-लक्ष्मी योजनाओं के क्रांतिकारी प्रभावों का उल्लेख करते हुए बताया गया कि केन्द्र और राज्य सरकारों की योजनाओं से प्रदेश के लिंगानुपात में प्रभावशाली सुधार हुआ है।

आयोग के प्रमुख सचिव श्री मुकेश चंद गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत किया। आभार प्रदर्शन आयोग के उप सचिव श्री डी.एस. परमार ने किया। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण और मानव अधिकार विषय पर आधारित स्मारिका का विमोचन किया गया। आयोग की ओर से अतिथियों को स्मृति-चिन्ह भी भेंट किये गये।

सागर में पुलिस वैन-कंटेनर की भिड़ंत, 4 जवानों की मौत

गाड़ी काटकर शव निकाले, नक्सल ऑपरेशन के लिए गए थे, पुलिस का डोंग सुरक्षित



सागर (नप्र)। सागर के नेशनल हाईवे-44 पर बांदरी के पास बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार कंटेनर और पुलिस के वाहन में आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे में पुलिस वाहन में सवार 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है, जिसे एयरलिफ्ट कर दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं, टीम में शामिल डोंग सुरक्षित है।

जानकारी के अनुसार मुरैना जिले का बम निरोधक दस्ता और डोंग स्कॉड बालघाट में ड्यूटी पर तैनात था। पुलिसकर्मों नक्सल विरोधी अभियान में शामिल हुए थे। वहां से वे बीड़ी-डीएस वाहन में सवार होकर वापस मुरैना लौट रहे थे। इसी दौरान

नेशनल हाईवे पर बांदरी के पास झिंझनी घाटी पर सामने से आ रहे कंटेनर से पुलिस वाहन की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डोंग मास्टर समेत चार जवानों की जान चली गई।

जानकारी के मुताबिक, एनएच- 44 पर अंडरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। इस कारण से बांदरी के पास हाईवे का ट्रैफिक वन वे हो गया है। इसी के चलते आमने-सामने से भिड़ंत हो गई।

तीन पुलिसकर्मों भिंड, एक मुरैना का था

1. आरक्षक प्रद्युम्न दीक्षित, फूप, भिंड
2. अनिल कौरव, टैकोन गांव, भिंड
3. विनोद शर्मा, पुलिस लाइन, भिंड
4. परिमल सिंह तोमर, नखती अंबाह, मुरैना

मुख्यमंत्री ने सागर में सड़क दुर्घटना में 4 पुलिसकर्मियों के निधन पर व्यक्त किया शोक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर जिले में सड़क दुर्घटना में 4 पुलिसकर्मियों के निधन पर गहन शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि आज सुबह नक्सल विरोधी अभियान से ड्यूटी कर लौट रहे पुलिस दल की भीषण सड़क दुर्घटना में 4 पुलिसकर्मियों के निधन का समाचार अत्यंत हृदय विदारक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिवंगत पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ईश्वर से दिवंगत पुलिसकर्मियों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने सड़क दुर्घटना में घायल पुलिसकर्मियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।

पहले रोका... फिर जीतू पटवारी समेत 5 नेता को जंगल भेजा

सिंगरौली में 6 लाख पेड़ों की कटाई पर हंगामा कांग्रेस बोली-प्रशासन अडाणी के पक्ष में

सिंगरौली (नप्र)। सिंगरौली जिले के बासी बेरहवा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रही कथित पेड़ कटाई को लेकर कांग्रेस का जोरदार विरोध बुधवार को देखने को मिला। घिरौली गांव के पास दो घंटे तक सड़क पर चले धरने के बाद शाम करीब 4:30 बजे प्रशासन ने जीतू पटवारी, ओंकार मरकाम,



प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अगर सब कुछ नियमों के तहत हो रहा है तो जांच टीम को जंगल देखने और आदिवासी परिवारों से मिलने से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार और अडाणी समूह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जिला प्रशासन एकतरफा कार्रवाई कर रहा है।

अजय सिंह बोले- अनुमति नहीं मिली तो धरना जारी रहेगा- पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चुरहट विधायक अजय सिंह ‘राहुल भैया’ ने प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल अपनी जांच टीम को अंदर भेजना चाहती थी, लेकिन पुलिस अनुमति नहीं दे रही थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अनुमति मिलने तक धरना जारी रहेगा।

800 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात, सुरक्षा कड़ी- स्थिति को देखते हुए घिरौली गांव से आगे जाने वाले मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सिंगरौली समेत सीधी, रीवा, सतना, मऊगंज, भोपाल, मंडला और छिंदवाड़ा से पुलिस बल बुलाया गया। कुल 800 से अधिक पुलिसकर्मी और क्यूआरएफ मौके पर तैनात हैं। प्रशासन के अनुसार स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है।

बड़ी कांग्रेस टीम, कटाई रोकने की मांग- जांच और विरोध टीम में जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, अजय सिंह, विक्रांत भूरिया, जयवर्धन सिंह, मीनाक्षी नटराजन, हेमंत कटारे, बाला बच्चन, हिना कावरे, ओंकार मरकाम और कमलेश्वर पटेल शामिल हैं। सभी नेताओं ने पेड़ कटाई पर तुरंत रोक और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बड़े पैमाने पर पेड़ कटाई से हरियाली खत्म हो जाएगी और भविष्य में प्रदूषण व जलसंकट जैसी गंभीर समस्याएं खड़ी होंगी। कांग्रेस की टीम पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर अपने शीर्ष नेतृत्व को सौंपेगी।

पटवारी का आरोप- प्रशासन अडाणी के पक्ष में-

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अगर सब कुछ नियमों के तहत हो रहा है तो जांच टीम को जंगल देखने और आदिवासी परिवारों से मिलने से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार और अडाणी समूह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जिला प्रशासन एकतरफा कार्रवाई कर रहा है।

ट्रेक्टर नहर में गिरा, तीन किसानों की मौत

टूटी पुलिया पर अंधेरे में नहीं देखा रास्ता, ट्रॉली के नीचे दबे थे शव



खेत में पानी दे रहे किसानों ने देखा

हादसा अंधेरे में हुआ, इसलिए किसी को तुरंत इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। पास के खेतों में पानी दे रहे कुछ किसानों की नजर नहर में उल्टे पड़े ट्रैक्टर-ट्रॉली पर पड़ी। पास जाकर देखा तो तीनों किसान ट्रैक्टर के नीचे दबे हुए थे। ग्रामीणों ने तुरंत लहार पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही टीआई शिवसिंह यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

ट्रेक्टर के नीचे दबे मिले शव

पुलिस और ग्रामीणों की मदद से नहर के पानी में फंसे ट्रैक्टर को हटाया गया। इसके नीचे दबे तीनों किसानों के शव बाहर निकाले गए। ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे दबने और पानी में डूबने से तीनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।

भगवान महाकाल को अब नहीं चढ़ेगी भारी-भरकम फूलमाला

प्रशासक ने 1 जनवरी से प्रतिबंध लगाया, 500 से 2100 रुपए तक बिकती थी

उज्जैन (नप्र)। श्री महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग पर भारी भरकम चढ़ने वाली फूल माला (अजगर माला) और मुण्डमाल पर मंदिर समिति ने प्रतिबंध लगा दिया है। एएसआई और जीएसआई की गाइड लाइन का ध्यान रखते हुए करीब 10 किलो से अधिक वजनी मालाओं पर शिवलिंग क्षरण रोकने के लिए मंदिर समिति ने ये फैसला किया है। 1 जनवरी से कोई भी भक्त भगवान महाकाल को 10 से 15 किलो वजनी माला अर्पित नहीं कर सकेगे।

ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 1 जनवरी 2026 से भगवान महाकाल को चढ़ने वाली फूलों की बड़ी व भारी माला अर्पित करने पर रोक लगा दी है। मंदिर प्रशासक के आदेश के बाद आगामी नए वर्ष के पहले दिन से इसे पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

इसके लिए अभी महाकाल मंदिर परिसर में उद्घोष हो रहा है कि भगवान के लिए अजगर माला नहीं खरीदें। साथ ही कक्ष से भक्तों को नए नियम की जानकारी देने के लिए लगातार उद्घोषणा भी



की जा रही है। मंदिर के आसपास फूल प्रसाद की दुकान संचालित करने वाले व्यवसायियों को मंदिर समिति ने बता दिया है कि फूलों की भारी व बड़ी माला ना तो बनाए और न ही विक्रय करें। भक्त पुजारी को देते थे चढ़ाने के लिए- 500 से 2100 रुपए तक बिकने वाली इन अजगर

मालाओं को भक्त खरीद कर शिवलिंग को अर्पित कर रहे थे। भक्त पुजारी को देते और पुजारी भगवान महाकाल को पहना देते थे। मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि महाकाल मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ने वाले भारी अजगर माला पर आगामी एक जनवरी से प्रतिबंधित कर दिया है।

500 से 2100 रुपए में मिलती 1 माला

पिछले कुछ वर्षों से महाकाल मंदिर के बाहर फूलों की दुकान पर 500 से 2100 रुपए में मिलने वाली अजगर माला को भक्त खरीदकर भगवान को अर्पित कर रहे थे। ये माला फूलों की मोटी व बड़ी माला होती है, जिनका 10 से 15 किलो तक होता था।

नया नियम लागू होने के बाद मंदिर के विभिन्न द्वारों पर तैनात गाई भक्तों द्वारा भगवान को अर्पण करने के लिए लाई जा रही पूजन सामग्री की जांच करेंगे। बड़ी व भारी फूल माला को गेट पर ही अलग रखवा दिया जाएगा।

क्षरण रोकने के लिए किए उपाय

सुप्रीम कोर्ट ने ज्योतिर्लिंग महाकाल के क्षरण की जांच तथा उसे रोकने के उपाय करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की टीम गठित की थी। विशेषज्ञों ने ज्योतिर्लिंग की सुरक्षित रखने के लिए कई सुझाव दिए। इसमें एक सुझाव भगवान महाकाल को फूलों की छोटी माला तथा समिति मात्रा में फूल अर्पण का था।